S.No.	Name of the Project	Project Cost (Rs. in lacs)	Scheduled Date of Completion
21.	Improvement of Water Supply Scheme.	4,555.00	Sept., 1998
22.	Sewerage Treatment Plant on Mysore Road.	5,212.00	—
23.	Sewerage Treatment Plant-Yelahanka.	3,924.80	—
24.	Investment in Energy saving opportunities at BWSSB pumping stations.	1,617.35	—
25.	Augmentation of water supply by ground water resources.	820.00	—
26.	Improvement of slum settlements in Bangalore.	150.00	—
27.	Establishment of seven satellite and one mega agriculture markets around Bangalore-Phase.I	3,929.00	—
28.	Re-modelling of Shivajinagar Bus stand with car parking facilities.	550.09	—
29.	Construction of Trunk Terminal on Hosur Road.	2,364.00	—
	TOTAL:	6,3878.85	—

Regularisation of Unauthorised Colonies in Delhi

2888. SHRI AMAR SINGH: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proposal received from Delhi Administration for the regularisation of unauthorised colonies in Delhi has not been approved as yet;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) by when these are proposed to be regularised?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Hon'ble High Court of Delhi has restrained the respondents, including Union of India, from taking any decision to regularise the unauthorised colonies in Delhi till further orders. The

मध्य प्रदेश में पेयजल की योजना

2889. **श्री राधाकृष्ण मालवीय:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश के बीस हजार से कम आबादी वाले नगरों की पीने के पानी की आपूर्ति की योजनाएं स्वीकृति हेतु विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन नगरों की योजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने 3637.22 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 44 स्कीमें भेजी हैं, जो वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए॰ यू॰ डब्ल्यू॰ एस॰ पी॰) के तहत केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए विचाराधीन है।

(ख) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत स्कीमों का अनुमोदन शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की केन्द्रीय योजना के तहत धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय वृहत नगर योजना के अंतर्गत अहमदाबाद को लाना

2890. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने सरकार से अहमदाबाद गांधीनगर को (ग्रेटर) वृहत अहमदाबाद का दर्जा देने और इसे राष्ट्रीय वृहत नगर योजना के अन्तर्गत लाने के लिए एक अभ्यावेदन प्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) ग्रेटर अहमदाबाद हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(घ) गुजरात सरकार द्वारा किस अनुपात में व्यय किया जाएगा और ग्रेटर अहमदाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी नगर पालिकाओं को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उसने अहमदाबाद गांधीनगर को बृहत ग्रेटर अहमदाबाद का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार को कोई अभ्यावेदन प्रेषित नहीं किया है।

तथापि, गुजरात सरकार ने भारत सरकार से अहमदाबाद को मेगा सिटी स्कीम के अन्तर्गत शामिल किए जाने का अनुरोध किया है। केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मेगा शहरों में आधारिक संरचना के विकास के लिए 1991 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले शहरों में शामिल किया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार अहमदाबाद (शहरी क्षेत्र) की जनसंख्या 3.31 मिलियन है इसलिए अहमदाबाद को बृहत नगर योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। इस स्थिति से राज्य सरकार को अवगत करा किया गया था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठता।

DDA Samadhan Scheme

2891. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to grant amnesty on a broad basis by DDA to defaulters, who have defaulted in paying their regular instalments of DDA Flats, under the "Samadhan Scheme" as recently announced;

(b) if so, the details thereof alongwith the exact terms and conditions;

(c) by when, the above scheme is likely to be launched; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) to (c) The Government has decided to allow the defaulter allottees of DDA flats to settle their over-dues to DDA by giving 37% relief in penalty upto 31.12.98 as per the terms and conditions laid down in hire purchase Penalty Relief Scheme 1997, under the "Samadhan Scheme". DDA has been asked to open special counters for the convenience of the concerned allottees and to give adequate publicity to encourage the maximum number of people to pay their dues by Categorically stating that this would be the last and final relief scheme and if the defaulter allottees fail to avail of this opportunity to settle their over-dues to DDA their allotment shall be cancelled by following the prescribed procedure by DDA.

(d) Does not arise in view of reply to (a) to (c) above.

Allotment of Plots by DDA

2892. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether DDA Slum Wing had announced any scheme in 1985 for registration of flats;

(b) whether any announcement was made in the year 1989 for changing registration from flats to plots;

(c) if so, the number of applicants who opted for registration from flats to plots together with number of applicants who have been allotted plots, so far; and

(d) by when all the applicants are likely to be allotted plots?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.